RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 18 NOVEMBER TO 24 NOVEMBER 2020 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 06 ■ अंक 13 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

शेयर मार्केट 44000 के पार उच्चतम स्तर पर हुआ बंद Page 2

जीएसटी पंजीयन प्रक्रिया को और सख्त करने जा रही है सरकार Page 5

किसानों के लिए होने वाले रिसर्च में ड्रोन का होगा उपयोग, सरकार से मिली हरी झंडी Page 7

editoria!

RCEP: सबसे बड़ा समझौता

दस आसियान देशों का चीन, जापान, साउथ कोरिया, न्यू जीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर किया गया आरसीईपी (रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकनॉमिक पार्टनरशिप) समझौता दीर्घकालिक स्तर पर वैश्विक व्यापार के स्वरूप को प्रभावित करने वाली बेहद महत्वपूर्ण घटना है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से होता है कि समझौते में शामिल पंद्रहों देश मिलकर ग्लोबल जीडीपी के करीब 30 फीसदी हिस्से को कवर कर लेते हैं। समझौते को लेकर बातचीत हालांकि 2012 से ही चल रही थी और शुरुआती सालों में इसमें भारत भी शामिल था, लेकिन सात साल विभिन्न दौर की बातचीत चलने के बाद जब चीजें निर्णायक चरण में पहुंच कर ठोस शक्ल लेने लगीं तो भारत को अहसास हुआ कि लाख कोशिशों के बावजूद प्रस्तावित समझौते को एक हद से ज्यादा बदला नहीं जा सकता और अपने अंतिम रूप में यह भारतीय खेती तथा कृषि आधारित उद्योगों को बुरी तरह प्रभावित करेगा। लिहाजा पिछले साल इस समझौते से उसने खुद को बाहर कर लिया। बावजूद इसके, दुनिया के इस सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावों से खुद को अछूता रखना भारत के लिए संभव नहीं होगा। पूर्वी देशों के बाजार में संभावनाएं तलाशने का काम भारत अभी ठोस ढंग से शुरू भी नहीं कर पाया है, जो इस समझौते के लागू हो जाने के बाद और मुश्किल हो जाएगा। दूसरी और इससे भी बड़ी चुनौती इन देशों के सस्ते माल से विश्व बाजार में अपनी जगह सुरक्षित रखने की होगी। भारत भले ही आरसीईपी समझौते का हिस्सा न हो, पर इन सभी देशों से उसके अच्छे व्यापारिक रिश्ते हैं। चूंकि यह समझौता विभिन्न देशों के लिए एक-दूसरे से कच्चा और अर्धनिर्मित माल खरीदना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना देगा, लिहाजा इसका सीधा परिणाम यह होगा कि भारत अपनी तरफ से टैक्स में अतिरिक्त छूट न दे तो भी इनका माल भारत के बाजार में पहले से कम कीमत पर आने लगेगा। स्वाभाविक रूप में इससे भारतीय कंपनियों की चुनौतियां बढ़ जाएंगी। यह स्थिति दुनिया के अन्य बाजारों में भी भारतीय कंपनियों के उत्पाद के लिए कॉम्पिटिशन में टिके रहना मुश्किल बना सकती है। अच्छी बात यह है कि यह समझौता तत्काल लागू नहीं होने जा रहा। सभी संबंधित देशों को अपनी-अपनी संसदों से इसकी पुष्टि करानी होगी, जिसके लिए 2024 तक की समय सीमा रखी गई है। इस बीच आरसीईपी में भारत की वापसी के लिए भी दरवाजा खुला है। यानी भारत चाहे तो कुछ समय बाद भी समझौते का हिस्सा बन सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत के पास आरसीईपी समझौते के संभावित प्रभावों पर बारीकी से विचार करते हुए इसके दुष्प्रभावों से बचने के उपाय तलाशने और जरूरी लगे तो आवश्यक सावधानियां बरतते हुए समझौते में शामिल होने का भी मौका बचा हुआ है। उम्मीद करें कि भारत इस मौके का सही उपयोग करते हुए वक्त रहते उपयुक्त कदम उठा लेगा।

ओपेक और उसके सहयोगी देशों ने कच्चे तेल की मांग में कमी आने की आशंका जताई : रिपोर्ट

नई दिल्ली। एजेंसी

तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और इसके सहयोगी देशों ने साल, 2021 के दौरान कच्चे तेल की मांग में कमी आने की आशंका जताई है। एक न्यूज एजेंसी ने खुफिया दस्तावेज के मुताबिक, ओपेक ने अपने संशोधित आंकलन के पहले लगाए गए अनुमान की अपेक्षा मांग में कमी रहने की बात कही है। इसके चलते अगले साल कच्चे तेल की सप्लाई में कटौती की संभावना बढ़ गई है।

ओपेक की ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी (जेटीसी) की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2021 में तेल की मांग में 6.2 मिलियन बैरल प्रति दिन के हिसाब से इजाफा होने की उम्मीद है। यह पहले लगाए गए अनुमान से 0.3 मिलियन बैरल कम है। ओपेक और उसके सहयोगी देशों के बीच बीते सोमवार को एक वर्चुअल बैठक हुई। यह बैठक मंगलवार को होने वाली मिनिस्ट्रियल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक से ठीक पहले हुई है। इस आगामी बैठक में नीतिगत फैसले लिए जाने की संभावना है।

इससे पहले, संगठन ने जनवरी से उत्पादन में दो मिलियन बीपीडी तक इजाफा करने की बात कही थी, जो वैश्विक खपत का दो फीसदी है। लेकिन मांग में कमी की आशंका के बीच संगठन उत्पादन बढ़ाने पर फिर से विचार कर रहा है। बता दें कि इस साल संगठन ने उत्पादन में रिकॉर्ड कटौती की है।

सूत्रों के मुताबिक, ओपेक और इसके सहयोगी देश पहले से निर्धारित 7.7 मिलियन बीपीडी उत्पादन को तीन से छह महीने तक बनाए रखने पर विचार कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर उत्पादन में कटौती को मार्च, 2021 तक बनाए रखा गया, तो ओईसीडी का कॉमर्शियल तेल भंडार 73 मिलियन बैरल तक गिर सकता है। इस कटौती को अगर जून तक तक जारी रखा गया, तो यह भंडार 21 मिलियन बैरल तक गिर जाने की संभावना है।

बता दें कि 2021 के लिए उत्पादन नीति पर विचार करने के लिए ओपेक और इसके सहयोगी देश 30 नवंबर और एक दिसंबर को बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में नीतिगत फैसले लिए जाने हैं।

अगले साल 13 फीसदी रहेगी भारत की विकास दर

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। वैश्विक रिसर्च फर्म गोल्डमैन सॉक्स ने आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी को देखते हुए चालू वित्तवर्ष के विकास दर अनुमान में सुधार किया है। एजेंसी ने कहा है कि इस साल जीडीपी में करीब 10 फीसदी गिरावट रहेगी, तो अगले साल यह 13 फीसदी की दर से आगे बढ़ेगी। गोल्डमैन सॉक्स के मुताबिक, अक्तूबर में परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) की वृद्धि दर 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 58 अंक तक पहुंच गया। इतना ही नहीं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) भी छह महीने में पहली बार बढ़ा है और सितंबर में 0.2 फीसदी की तेजी आई है। सुधार के इन संकेतों को देखते हुए 2020-21 के विकास दर अनुमानों में भी सुधार करना होगा। फर्म ने कहा कि चालू वित्तवर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.3 फीसदी की गिरावट आ सकती है। सितंबर में एजेंसी ने 14.8 फीसदी गिरावट का अनुमान जताया था। अब इसमें 4.5 फीसदी का सुधार किया है। फर्म ने कहा कि अगले वित्तवर्ष 2021-22 में भारती की जीडीपी 13 फीसदी की तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी। यह दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगी।

मूडीज ने भी सुधारा अनुमान

मूडीज ने भी सुधारा अनुमान

वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था में आए तेज सुधारों को देखते हुए चालू वित्तवर्ष के लिए विकास दर अनुमान में सुधार किया था। मूडीज ने कहा था कि सितंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6 फीसदी की गिरावट आ सकती है, लेकिन पिछले सप्ताह इसे सुधारकर 8.9 फीसदी कर दिया था। इसके अलावा आरबीआई ने भी चालू वित्तवर्ष में जीडीपी में 9.5 फीसदी गिरावट का अनुमान लगाया है। हालांकि, रेटिंग एजेंसियों का कहना है कि वित्तवर्ष की दूसरी छमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड तेजी आएगी और अगले साल यह सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

ओएनजीसी ने सात, ऑयल इंडिया ने चार खंडों के लिये अनुबंध पर हस्ताक्षर किया

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकारी कंपनी ओएनजीसी ने सात और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने चार तेल एवं गैस खंडों के लिये अनुबंध पर मंगलवार को हस्ताक्षर किये। ये खंड खुले क्षेत्र की लाइसेंस नीति (ओएलएपी) की पांचवीं दौर की बोली में नीलाम किये गये थे। इस दौर में निजी क्षेत्र की भागीदारी के बीच सरकारी कंपनियों ने इन खंडों को प्राप्त किया था। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हस्ताक्षर समारोह में कहा कि आखिरी दौर की बोली के साथ ही सरकार तेल व गैस की खोज के लिये पिछले चार साल में 1.56 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नीलाम कर चुकी है। इससे पहले पिछले दो दशक में नयी खोज लाइसेंस नीति के नौ दौर तथा उससे पूर्व के दौर में 90 हजार किलोमीटर नीलाम किये गये थे। प्रधान ने कहा कि वह प्रतिभागी कंपनियों से तेल एवं गैस की खोज के काम में तेजी लाने की अपेक्षा रखते हैं, ताकि देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। प्रधान ने कहा कि लाल फीता शाही और तेल एवं गैस की तलाश में कई प्रकार की मंजूरियों के चलते पहले कई बार समयसीमा को बढ़ाया जा चुका है। उन्होंने तेल एवं गैस की खोज करने वालों से नियामकीय परिस्थितियां बेहतर बनाने के बारे में सुझाव आमंत्रित करते हुए कहा, ''यदि आपको अधिक मदद की जरूरत है तो हमें बतायें।''

शेयर मार्केट 44000 के पार उच्चतम स्तर पर हुआ बंद

मुंबई। एजेंसी

कोविड-19 के टीके के सफल परीक्षण की खबर का असर बुधवार को शेयर बाजार पर नजर आया। आज बीएसई का सेंसेक्स 44,000 स्तर के पार ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ। सेंसेक्स 227 अंकों की तेजी के साथ 44,180.05 और निफ्टी 64.05 अंक मजबूत होकर 12,938.25 अंक पर बंद हुआ। आज सुबह बीएसई का सेंसेक्स नई ऊंचाई के साथ 44,000 के पार खुला। सेंसेक्स 82.43 अंक उछलकर 44,035.14 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी 22 अंकों की तेजी के साथ 12,896.50 के स्तर पर कारोबार करते दिखा। विदेशी कोषों की आवक जारी रहने और दूसरे एशियाई बाजारों से सकारात्मक संकेत मिलने से बाजार को बल मिला। इस दौरान 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर 44,051.66 को छूने के बाद 55.15 अंक या 0.13 प्रतिशत बढ़कर 44,007.86 पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह एनएसई निफ्टी 19.10 अंक या 0.15 प्रतिशत बढ़कर 12,893.30 पर

पहुंच गया।

मंगलवार को ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ सेंसेक्स

बीएसई का सेंसेक्स मंगलवार को ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ। सेंसेक्स 314 अंकों की बढ़त के साथ 43,952 और निफ्टी करीब 94 अंकों की तेजी के साथ 12,874.20 के स्तर पर बंद हुआ। एक समय सेंसेक्स 315 अंकों की तेजी के साथ 44,161 के स्तर को छू गया। पहली बार सेंसेक्स ने 44000 के रिकॉर्ड हाई स्तर को पार किया।

बीपीसीएल में सरकारी हिस्सेदारी खरीद सकती है वेदांता, दाखिल किया ईओआई

नई दिल्ली। एजेंसी

वेदांता ग्रुप (Vedanta Group) ने बुधवार को कहा कि उसने भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में सरकार की हिस्सेदारी खरीदने के लिए प्रारंभिक अभिरुचि पत्र (expression of interest) दाखिल कर दिया है। भारत की दूसरे सबसे बड़े ईंधन रिटेलर कंपनी में वेदांता की दिलचस्पी उसके अपने मौजूदा तेल और गैस कारोबार के साथ तालमेल रहने के कारण है। सरकार बीपीसीएल में अपनी पूरी 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है और इसके लिए अभिरुचि पत्र (ईओआई) दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर थी।

कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, 'बीपीसीएल के लिए वेदांता का ईओआई हमारे मौजूदा तेल और गैस कारोबार के साथ संभावित तालमेल का मूल्यांकन

करने के लिए है।' सरकार ने बोली लगाने के समाप्ति के मौके पर कहा था कि कई अभिरुचि पत्र प्राप्त हुए हैं। हालांकि, उसने बोली लगाने वालों की पहचान उजागर नहीं की।

बिजनस में तालमेल

इससे पहले वेदांता रिसोर्सेज के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा था कि उनकी कंपनी बीपीसीएल के लिए बोली लगाने पर विचार करेगी क्योंकि दोनों कंपनियों के बिजनस में तालमेल है। इस बिक्री में असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी में बीपीसीएल की 61.65 फीसदी हिस्सेदारी शामिल नहीं है। सरकार ने इस वित्त वर्ष के दौरान विनिवेश से 2.1 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। बुधवार को बीपीसीएल का शेयर दोपहर बाद करीब ढाई बजे 3.46 फीसदी की गिरावट के साथ 381 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

काम कर गया आत्मनिर्भर भारत अभियान, करोड़ों में पहुंची खादी की बिक्री

नई दिल्ली। एजेंसी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का असर खादी की बिक्री पर देखने को मिला है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील की थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि खादी की बिक्री करोड़ों में पहुंच गई है। खादी के सेल्स आउटलेट पर बिक्री में काफी जबरदस्त सेल देखने को मिली है। कनॉट प्लेस, दिल्ली में मौजूद खादी इंडिया के मुख्य केंद्र पर दिवाली से एक दिन पहले यानी 13 नवंबर को करीब 1.11 करोड़ रु की खादी की सेल्स दर्ज हुई। ये 2020 में सबसे अधिक बिक्री का आंकड़ा है।

4 बार सेल्स 1 करोड़ रु के पार रही सेल

इस साल 2 अक्टूबर के बाद से 4 बार खादी की सेल 1 करोड़ रु से अधिक की रही है। इस बात का खुलासा एमएसएमई मंत्रालय की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज में हुआ है। एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष 2 अक्टूबर से अब तक केवल 40 दिनों की अवधि में खादी की सिंगल-डे बिक्री का आंकड़ा नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के प्रमुख खादी इंडिया आउटलेट में 4 बार 1 करोड़ रुपये से अधिक रहा है। 13 नवंबर को इस आउटलेट की कुल बिक्री 1.11 करोड़ रुपये रही, जो इस साल की सबसे अधिक सिंगल-डे बिक्री है।

कब-कब छुआ 1 करोड़ रु का आंकड़ा लॉकडाउन के बाद व्यावसायिक गतिविधियां फिर से शुरू हुईं। इसके बाद खादी की बिक्री का आंकड़ा इस साल गांधी जयंती (2 अक्टूबर) को 1.02 करोड़ रुपये पर पहुंच गया था। इसके बाद 24 अक्टूबर को 1.05 करोड़ रुपये और 7 नवंबर को 1.06 करोड़ रुपये की खादी की बिक्री हुई। इससे पहले 2018 में भी खादी की सिंगल-डे बिक्री चार मौकों पर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा रही थी। 2018 में 13 अक्टूबर को 1.25 करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी, जो उस साल की उच्चतम सिंगल-डे बिक्री थी। जहां तक आज तक की हाइएस्ट सिंगल-डे बिक्री का सवाल है तो 2 अक्टूबर 2019 को खादी की 1.27 करोड़ रुपये दर्ज की गई थी। पीएम मोदी की अपील का असर खादी की इस रिकॉर्ड बिक्री का श्रेय पीएम मोदी को दिया जा राह है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना के मुताबिक खादी की खरीदारी के लिए देश को प्रेरित पीएम मोदी ने ही किया। इस बिक्री से खादी के कारीगरों की मदद हो रही है जिस पर उन्होंने खुशी जताई। खादी के कारीगर कोरोना संकट में लगातार काम करते रहे। वोकल फॉर लोकल पीएम मोदी ने मई में कोरोना महामारी के बीच देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान और वोकल फॉर लोकल का ऐलान किया था। तब उन्होंने कहा था कि कोरोना महामारी के दौरान हमें लोकल ने ही बचाया है। वोकल फॉर लोकल का मतलब है स्थानीय चीजों के प्रोडक्शन और खरीदारी को बढ़ावा देना ताकि देश के उद्यियों को फायदा मिले। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम था। उसी दौरान पीएम ने 20 लाख करोड़ रु के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया था।

रिलायंस रिटेल ने ऑनलाइन फर्नीचर कंपनी अर्बन लैडर का किया अधिग्रहण

नई दिल्ली। एजेंसी

रिलायंस इंडस्ट्रीज की खुदरा इकाई ने ऑनलाइन फर्नीचर कंपनी अर्बन लैडर की 96 प्रतिशत हिस्सेदारी का 182 करोड़ रुपये में अधिग्रहण किया है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में यह जानकारी दी। सूचना में कहा गया है, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लि. (आरआरवीएल) ने अर्बन लैडर होम डेकोर सॉल्यूशंस प्राइवेट लि. के इक्विटी शेयरों का 182.12 करोड़ रुपये नकद में अधिग्रहण किया है। इस निवेश के जरिये उसने अर्बन लैडर की 96 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। आरआरवीएल के पास अर्बन लैडर की शेष हिस्सेदारी खरीदने का भी विकल्प होगा, जिससे उसकी कुल हिस्सेदारी 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी की हो जाएगी। इसके अलावा आरआरवीएल ने कंपनी में 75 करोड़ रुपये का और निवेश करने का प्रस्ताव किया है। कंपनी ने कहा कि यह निवेश दिसंबर, 2023 तक पूरा हो जाएगा। इस अधिग्रहण से रिलायंस इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स बाजार में अपनी उपस्थिति को और मजबूत कर सकेगी और साथ ही उपभोक्ताओं के लिए अपने उत्पादों की पेशकश बढ़ा सकेगी। साथ ही इससे वह ई-कॉमर्स क्षेत्र की बड़ी कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट को भी चुनौती पेश कर सकेगी। बयान में कहा गया है कि इस निवेश से समूह की डिजिटल और नव वाणिज्य पहल को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

रुपये में लगातार तीसरे दिन तेजी, 27 पैसे बढ़कर 74.19 रुपये प्रति डॉलर हुआ

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

रुपये में लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में बुधवार को भी तेजी रही। घरेलू शेयर बाजार में तेजी और अमेरिकी मुद्रा के कमजोर होने के बीच रूपये की विनिमय दर 27 पैसे की तेजी के साथ 74.19 प्रति डॉलर पर बंद हुई। बाजार सूत्रों ने कहा कि मुख्य प्रतिद्वन्द्वी मुद्राओं की तुलना में डॉलर के कमजोर होने तथा विदेशी निधियों की ओर से पर्याप्त निवेश बढ़ने से निवेशकों की धारणा रुपये में मजबूत हुई। अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया 74.49 पर खुला और दिन के कारोबार के दौरान 74.09 के दिन के उच्च स्तर तथा 74.52 के निम्न स्तर को छूने के बाद अंत में अपने पिछले बंद भाव के मुकाबले 27 पैसे की पर्याप्त तेजी को दर्शाता 74.19 प्रति डॉलर पर पर बंद हुआ। मंगलवार को रुपया 16 पैसे सुधरकर 74.46 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर सूचकांक 0.21 प्रतिशत गिरकर 92.22 रह गया। घरेलू मोर्चे पर बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 227.34 अंक बढ़कर 44,180.05 अंक पर बंद हुआ। शेयर एक्सचेंज के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशक पूंजी बाजार में शुद्ध लिवाल बने रहे और उन्होंने मंगलवार को 4,905.35 करोड़ रुपये के शेयरों की खरीद की। इस बीच कच्चा तेल का अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 1.01 प्रतिशत की तेजी के साथ 44.19 डॉलर प्रति बैरल पर रहा।

जीएसटी पंजीयन प्रक्रिया को और सख्त करने जा रही है सरकार

धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्र और राज्य सरकारें फर्जी बिल के मामलों में हो रही वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के पंजीयन की प्रक्रिया और कानूनी उपाय कठिन बनाने पर काम कर रही हैं। इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इन मामलों पर चर्चा करने के लिए जीएसटी की विधि समिति की बुधवार को एक बैठक बुलाई गई है। जीएसटी परिषद की विधि समिति में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ कर अधिकारी शामिल हैं।

इन मुद्दों पर होगी चर्चा

समिति फर्जी बिलों से की जाने वाले धोखाधड़ी तथा जीएसटी पंजीयन की प्रक्रिया को जटिल बनाने पर चर्चा करेगी। इसके अलावा फर्जी बिलों पर लगाम लगाने के लिए जीएसटी अधिनियम में आवश्यक संशोधन समेत विभिन्न न्यायिक कदमों पर भी चर्चा करेगी।

निलंबन से संबंधित प्रावधान भी होंगे दुरुस्त

सूत्र ने कहा कि पंजीकरण के निलंबन से संबंधित प्रावधान को भी दुरुस्त किया जा सकता है, ताकि निलंबन व रद्द करने की प्रक्रिया को अधिक कुशल और तेज बनाया जा सके। यह अंततः समय पर धोखाधड़ी करने वालों को रोकने में मदद करेगा। सूत्र ने यह भी कहा कि धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में संलिप्त करदाताओं की पहचान करने के लिए डाटा का विश्लेषण करने वाली प्रौद्योगिकियों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

1,180 कंपनियों के मामले दर्ज

हाल ही में महानिदेशालय ने कर चोरी और फर्जी बिल के मामले में बड़ी कार्रवाई की थी। देशभर में सिर्फ चार दिनों तक की गई कार्रवाई में 1,180 कंपनियों के खिलाफ 350 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं, इस मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल, फर्जी बिल और हवाला रैकेट को देखते हुए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और सख्त कर दी गई है।

महानिदेशालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, ये गिरफ्तारियां कचरे और अलौह धातुओं के मलबे, रेडीमेड कपड़े, कृषि उत्पाद, दूध उत्पादों, मोबाइल, मानव श्रम आपूर्ति सेवाएं, विज्ञापन, सोना, चांदी और निर्माण सेवाओं में फर्जी बिल जारी करने को लेकर की गई हैं। इस मामले में शामिल लोगों और संस्थाओं पर जीएसटी चोरी, आयकर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोप हैं।

ऐसे होता है खेल

फर्जी कंपनियां नकली बिल बनाती हैं। कोई वस्तु भेजे बिना ही फर्जी ई-वे बिल भी तैयार किए जाते हैं और उसके बाद सरकार से आईटीसी का दावा किया जाता है। जीएसटी के तहत कच्चे माल और दूसरी खरीद पर दिए गए कर की वापसी होती है।

ब्रिक्स देशों ने कोविड-19 के बाद के दौर में समावेशी आर्थिक विकास, वृद्धि की बात की

नयी दिल्ली। एजेंसी

ब्रिक्स देशों ने कोरोना वायरस महामारी के चलते उत्पन्न चुनौतियों की जटिलता और अंतर्संबंध को मंगलवार को स्वीकार किया। उन्होंने आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने को लेकर बहुपक्षीय समन्वय और एकीकृत अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की अगुवाई करने की बात की। ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) ने यह भी कहा कि कोविड-19 के बाद के दौर में मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी आर्थिक विकास के साथ-साथ वृद्धि की ओर ले जाने के लिये अपने प्रयासों को मजबूत करेगा। पांच देशों के इस समूह के नेताओं ने रूस की मेजबानी में 12वीं शिखर सम्मेलन बैठक के बाद 2025 तक के लिये मॉस्को घोषणा, आतंकवाद रोधी रणनीति और ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी रणनीति को भी आपनाया। ब्रिक्स देशों के नेता 'रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा' ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य देशों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिये लगायी गयी व्यापारिक पाबंदियां व रुकावटें केवल लक्षित व अस्थायी हैं।

टैक्सपेयर पर नहीं डाला जाएगा अतिरिक्त बोझ

फॉर्म 26AS पर सरकार ने साफ की स्थिति

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सरकार ने साफ किया है कि फॉर्म 26एएस (Form 26AS) में दिखाए गए जीएसटी टर्नओवर (GST Turnover) के लिए टैक्सपेयर पर कोई अतिरिक्त अनुपालन बोझ नहीं डाला जाएगा। सरकार का कहना है कि फॉर्म 26 एएस में दिखाया जा रहा जीएसटी टर्नओवर केवल टैक्सपेयर्स की जानकारी के लिए है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने एक बयान में कहा कि फाइल किए गए जीएसटीआर-3बी फॉर्म और फॉर्म 26एएस में दिखाए गए जीएसटी में कुछ अंतर हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति करोड़ों रुपये का जीएसटी टर्नओवर दिखाए और एक रुपया भी इनकम टैक्स न दे। कुछेक ऐसे मामले हैं जिनका डेटा एनालिटिक्स में पता चला है।

सोशल मीडिया के कुछ वर्गों में ऐसी रिपोर्ट आ रही थी कि टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) में दिखाए गए टर्नओवर को फॉर्म 26एएस में अपलोड किए गए टर्नओवर से मिलान करना होगा। इससे टैक्सपेयर्स पर अनुपालन का बोझ बढ़ जाएगा। विभाग ने कहा कि सोशल मीडिया में आ रही इन अटकलों में कोई सच्चाई नहीं है और वे गुमराह करने वाली हैं।

क्या है फॉर्म 26AS?

यह आपका सालाना टैक्स स्टेटमेंट है। आप अपने पैन नंबर की मदद से इसे इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। अगर आपने अपनी आमदनी पर टैक्स चुकाया है या आपको हुई कमाई पर किसी व्यक्ति/संस्था ने टैक्स काटा है तो उसका जिक्र भी आपको फॉर्म 26AS में मिल जाता है। फॉर्म 26AS में न सिर्फ आपके सरकार को चुकाए गए कर की जानकारी होती है, बल्कि अगर आपने अधिक टैक्स चुका दिया है और आप उसका रिफंड फाइल करना चाहते हैं तो इस बारे में भी उसमें जिक्र होता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने साथ ही कहा हाल में ऐसा देखने में आया है कि कई जालसाजों ने फर्जी बिल बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठाने की कोशिश की है। इसके खिलाफ पिछले सोमवार से देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत चार दिन के भीतर 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी बिल की समस्या से निपटने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू का बहुत नुकसान होता है।

भारत में कोविड-19 के मामले 89 लाख के पार

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में कोविड- 19 से संक्रमित लागों की संख्या बुधवार को 89 लाख को पार कर गयी। हालांकि इनमें से 83 लाख से अधिक लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही मरीजों के ठीक होने की दर 93.52 प्रतिशत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह आठ बजे अद्यतन आंकड़ों के अनुसार एक दिन में कोविड-19 के 38,617 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या बुधवार को बढ़कर 89,12,907 हो गयी। इसमें कहा गया है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण से 474 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,30,993 हो गई। आंकड़ों के अनुसार देश में लगातार आठ दिनों से उपचाराधीन संक्रमितों की संख्या पांच लाख से कम है। अभी 4,46,805 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 5.01 प्रतिशत है। इसके अनुसार देश में अभी तक 83,35,109 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही मरीजों के ठीक होने की दर 93.52 प्रतिशत हो गई। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.47 प्रतिशत है। भारत में सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितम्बर को 40 लाख के पार चली गई थी। वहीं, कुल मामले 16 सितम्बर को 50 लाख, 28 सितम्बर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख और 29 अक्टूबर को 80 लाख के पार चले गए थे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार 17 नवम्बर तक कुल 12,74,80,186 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई, जिनमें से 9,37,279 नमूनों का परीक्षण मंगलवार को ही किया गया।

दिल्ली में छठ

कोरोना के फिर से जोर पकड़ने से मुश्किल में कारोबारी, 20 फीसदी महंगे हो गए सामान

नयी दिल्ली। एजेंसी

दिल्ली में लाखों पूर्वांचली रहते हैं। इन्होंने अपना गांव-घर भले ही छोड़ कर दिल्ली का दामन थाम लिया है, लेकिन अभी भी इनकी आस्था छठ के प्रति वही है। इसलिए दिल्ली में भी छठ पूजा खूब होने लगी है। जब छठ पूजा खूब होने लगी है तो छठ पूजा से जुड़े सामानों का बाजार भी खूब बढ़ गया है। इस साल कोरोना के साए में छठ पूजा हो रही है। छठ पूजा से जुड़े सामानों के कारोबार पर इसका क्या असर है।

50 से 60 फीसदी ही होगा काम

वर्षों से डाबरी मोड़ पर छठ पूजा से जुड़े सामान बेचने वाले प्रभाकर कुमार का कहना है कि इस छठ पूजा में बामुश्किल 50 से 60 प्रतिशत ही काम होने की उम्मीद है। लॉकडाउन में काफी लोग यूपी-बिहार चले गए हैं। वे अभी तक लौटे नहीं हैं। बहुत से लोग छठ पूजा के लिए ही अपने घर लौट गए हैं। वे अपने घरों पर ही धूमधाम से त्योहार मनाएंगे। अब जो लोग दिल्ली में हैं, वे अपनी छत, बालकोनी और आंगन में छठ पूजा करेंगे।

20 फीसदी महंगे हो गए पूजा से जुड़े सामान

प्रभाकर ने बताया कि कोविड-19 की वजह से छठ पूजा का सामान भी बाजारों में पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच सका है। इसकी वजह से पिछले साल के मुकाबले करीब 20 प्रतिशत महंगाई हो गई है। कोरोना के चलते काफी लोगों की नौकरी छूट गई है या फिर वेतन कम हो गया है, जिसके चलते उनकी जेब हल्की है। काम कम होने से कारोबारियों को बचत भी कम ही होगा।

दिल्ली में हर इलाके में सज गए छठ के बाजार

राष्ट्रीय राजधानी में लगभग सभी जगहों पर छठ के बाजार सज गए हैं। थोक कारोबारी प्रभाकर ने बताया कि बिहार के पटना, खगड़िया, छपरा, कोडरमा समेत कई शहरों से दिल्ली की आजादपुर मंडी, केशवपुर मंडी और शाहदरा मंडी में छठ पूजा का सामान आता है। इसके बाद जहां भी पूर्वांचल के लोग रहते हैं, वहां छोटे-बड़े बाजार लगते हैं। दिल्ली में छठ पूजा के करीब 50 बड़े बाजार, तो छोटे-मोटे मिलकर 300 बाजार लगते हैं।

छठ पूजा में उपयोग होने वाला सामान

बांस की बड़ी टोकरी, कच्चे बांस या पीतल के बने सूप, थाली, लोटा, दूध, गिलास, गन्ना, गुड़, अगरबत्ती, चावल, लाल सिंदूर, दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, सुथनी, सब्जी, शकरकंदी, नाशपाती, बड़ा नींबू, शरीफा, केला, शहद, पान, साबुत सुपारी, कैराव, कपूर, चंदन, मिठाई प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, खीर-पूड़ी. सूजी का हलवा, चावल के बने लड्डू आदि।

सोना-चांदी की कीमतों में हुई गिरावट

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय बाजारों में गोल्ड की कीमत में आज गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमतों में 357 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी आई. वहीं, चांदी के दाम में भी कमी देखी गई। एक किलोग्राम चांदी के दाम में 532 रुपये की गिरावट आई है। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 50,610 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी मंगलवार को 63,171 रुपये प्रति किलो पर थी।

सोने की नई कीमतें

दिल्ली सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 357 रुपये प्रति 10 ग्राम गिर गया। राजधानी दिल्ली में 99.9 ग्राम शुद्धता वाले सोने का नया भाव अब 50,253 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इसके पहले कारोबारी सत्र में सोने का भाव 50,610 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव बढ़कर 1,882 डॉलर प्रति औंस रहा है।

चांदी की नई कीमतें

चांदी की बात करें तो आज इसमें भी गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली सर्राफा बाजार में बुधवार को चांदी 532 रुपये प्रति किलोग्राम गिर गई। इसके दाम 62,639 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बुधवार को चांदी का भाव 24.57 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ।

क्यों आई सोने में गिरावट

एचडीएफसी सिक्योरिटी के सीनियर एनालिस्ट (कमोडिटीज) तपन पटेल ने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपये के 32 पैसे मजबूत होने के कारण दोनों कीमती धातुओं के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतों में कमी का असर भी भारतीय बाजारों पर पड़ा है। इसके अलावा कोविड-19 वैक्सीन को लेकर सकारात्मक घोषणाओं का असर भी सोने की कीमतों पर पड़ा है।

भारत को खाद्य वस्तुओं का निर्यात करने वाले विदेशी कारखानों का ऑडिट अनिवार्य करने का प्रस्ताव

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य वस्तुओं के आयात के नियमों में बदलाव की सिफारिश की है। उसने भारत को कुछ खास खास प्रकार के खाद्य उत्पादों का निर्यात करने वाली विदेशी इकाइयों की विनिर्माण सुविधाओं का पंजीकरण और ऑडिट अनिवार्य किए जाने का प्रस्ताव किया है। नियामक ने इस प्रस्ताव पर सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किए हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि इस मामले में एफएसएसएआई जोखिम के आकलन के बाद समय-समय पर ऐसे प्रकार के खाद्य उत्पादों की सूची जारी करेगा, जिन उत्पादों का भारत को निर्यात करने वाले विदेशी कारखानों का पंजीकरण और ऑडिट अनिवार्य किया जा सकता है। यह ऑडिट इस खाद्य प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा कराया जाएगा। विनियामक द्वारा जारी 'खाद्य सुरक्षा एवं मानक

:आयात: संशोधित विनियमन, 2020 के मसौदे के जरिए इस तरह के आयात के बारे में 2017 की नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के अनुसार, ऐसे निर्यातकों को भारत में इस प्राधिकरण के समक्ष पंजीकरण कराना होगा।

भारत के 'परम सिद्धि' को विश्व के 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में मिला 63वां स्थान

नयी दिल्ली। एजेंसी

राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग अभियान (एनएसएम) के तहत निर्मित 'परम सिद्धि' नामक भारतीय सुपर कंप्यूटर को विश्व के 500 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों की सूची में 63 वां स्थान प्राप्त हुआ है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। डीएसटी के सचिव आशुतोष शर्मा ने कहा, 'यह ऐतिहासिक क्षण है। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत, दुनिया की सबसे बड़ी अवसंरचनाओं के केंद्र में से एक है और यह परम सिद्धि-एआई की रैंकिंग ने साबित कर दिया है।' उन्होंने कहा, 'मुझे विश्वास है कि परम सिद्धि-एआई से हमारे राष्ट्रीय अकादमिक, विकास एवं अनुसंधान संस्थान मजबूत होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क पर फैले उद्योग और स्टार्टअप को भी लाभ होगा।' डीएसटी ने कहा कि एआई प्रणाली से स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ होगा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा।

एल एंड टी ने गगनयान मिशन के लिए समय से पहले दे दिया पहला हार्डवेयर

नई दिल्ली। एजेंसी

इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) ने कोविड-19 की पाबंदियों के बाद भी इसरो को गगनयान मिशन के लिये बूस्टर प्रणाली का पहला पुर्जा बना कर समय से पहले दे दिया है। कंपनी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। कंपनी ने बीएसई को बताया, "कोविड-19 के कारण लगायी गयी पाबंदियों के बाद भी दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ठोस प्रणोदक रॉकेट बूस्टर 'एस-200' के मध्य वाले हिस्से की आपूर्ति बिना किसी कमी के समय से पहले कर दी गयी है।"

कंपनी ने कहा कि इस हिस्से को एलएंडटी के पवई स्थित एयरोस्पेस विनिर्माण संयंत्र में बनाया गया है। यह भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान मिशन के लिये आवश्यक विस्तृत गुणवत्ता व समयसीमा की शर्तों को पूरा करता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने इसे देश के लिये दीपावली का उपहार घोषित करते हुए इसरो और एलएंडटी की टीम को बधाई दी।

उन्होंने कहा, "दोनों टीमों ने एक मानवयुक्त अंतरिक्ष यान मिशन के लिये आवश्यक सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए समय से पहले हार्डवेयर तैयार करने के लिये अथक श्रम किया है। हमें इस बात का भरोसा है कि इसरो के वैज्ञानिक, एलएंडटी के इंजीनियर और तकनीशियन मिलकर देश की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे।"

FD से ज्यादा ब्याज चाहिए तो कराएं TD, खूब मिलेगा ब्याज

नयी दिल्ली। एजेंसी

इसी नवंबर 2020 में ही प्रमुख बैंकों ने अपनी फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में फिर से कटौती कर दी है। स्थिति यह हो गई है कि अब एक साल की एफडी की ब्याज दरें 5 फीसदी के नीचे चली गई हैं। वहीं पोस्ट ऑफिस अभी भी एक साल से लेकर 5 साल तक की अपनी टाइम डिपॉजिट यानी टीडी में इन बैंकों से काफी ज्यादा ब्याज दे रहा है। अगर आप भी पोस्ट ऑफिस की टीडी का फायदा लेना चाहती हों तो यहां पर पूरी जानकारी ले सकती हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस एक स्कीम चलता है, जिसमें पैसा डबल होता है। आइये उसकी भी जानकारी लेते हैं।

पहले जानें प्रमुख बैंकों की ब्याज दरें -एचडीएफसी 1 साल से लेकर 2 साल की एफडी पर 4.90 फीसदी ब्याज दे रहा है। -एसबीआई 1 से लेकर 2 साल की एफडी पर 4.9 फीसदी दे रहा है। -एक्सिस बैंक 11 महीने 25 दिन से लेकर 1 साल 5 दिन वाली एफडी पर 5.15 फीसदी ब्याज दे रहा है। - आईसीआईसीआई बैंक 1 साल से लेकर डेढ़ साल की एफडी पर 4.9 फीसदी ब्याज दे रहा है।

पोस्ट ऑफिस की एफडी की ब्याज दरें पोस्ट ऑफिस भी एफडी करता है। लेकिन यहां पर इसको टाइम डिपॉजिट यानी टीडी कहा जाता है। पोस्ट आफिस में अगर कोई चाहे तो न्यूनतम 1000 रुपये की एफडी करा सकता है। वहीं अधिकतम कितने भी रुपये की एफडी यानी टीडी कराने की छूट है। जहां तक ब्याज दरों की बात है तो 1 साल लेकर 3 साल तक की टीडी पर इस वक्त 5.5 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है। वहीं 5 साल की टीडी पर इस वक्त 6.7 फीसदी ब्याज मिल रहा है। यह ब्याज दरें आज की तारीख में ज्यादातर बैंकों से काफी ज्यादा हैं।

पोस्ट ऑफिस की अन्य जमा योजनाओं की ब्याज दरें -पोस्ट ऑफिस बचत खाता में इस वक्त 4 फीसदी का ब्याज - पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना (एमआईएस) पर इस वक्त 6.6 फीसदी का ब्याज -किसान विकास पत्र (केवीपी) पर इस वक्त 6.9 फीसदी का ब्याज -सुकन्या समृद्धि योजना पर इस वक्त 7.6 फीसदी का ब्याज -वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर इस वक्त 7.4 फीसदी का ब्याज पोस्ट ऑफिस की पैसा दोगुना करने वाली एकलौती स्कीम पोस्ट ऑफिस की पैसा दोगुना करने वाली स्कीम का नाम है किसान विकास पत्र (केवीपी)। इस स्कीम में वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा दोगुना हो जाता है। किसान विकास पत्र देश के सभी डाकघरों से खरीदा जा सकता है। इस वक्त अगर केवीपी में निवेश किया जाए तो यह पैसा 124 महीने में डबल हो जाता है। केवीपी में न्यूनतम निवेश 1000 रुपये का किया जा सकता है। वहीं अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। इस वक्त केवीपी पर 6.9 फीसदी का ब्याज मिल रहा है। किसान विकास पत्र यानी केवीपी 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये और 50,000 रुपये के सर्टिफिकेट के रूप में खरीदा जा सकता है।

ट्रेड यूनियनों की 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल

किसानों के विरोध प्रदर्शन को देंगे समर्थन

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों में दस ने मंगलवार को कहा कि वे 26 नवंबर को अपनी राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल की घोषणा पर कायम हैं और साथ ही अगले हफ्ते होने वाले किसानों के दो दिन के विरोध प्रदर्शन को भी समर्थन देंगी। इस संबंध में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच और विभिन्न उद्योगों के स्वतंत्र मजदूर संघों ने 16 नवंबर 2020 को एक वर्चुअल बैठक भी की। संयुक्त मंच ने एक बयान में कहा कि यूनियनों को 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के लिए श्रमिकों का जबरदस्त समर्थन मिला है।

इस अभियान में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक), ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक), हिंद मजदूर सभा (एचएमएस), सेंटर ऑफ इंडियप ट्रेड यूनियंस (सीटू), ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी), ट्रेड यूनियन को-ऑर्डिनेशन सेंटर (टीयूसीसी), सेल्फ-एंप्लॉयड वीमेंस एसोसिएशंस (सेवा), ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस (एआईसीसीटीयू), लेबर प्रोगरेसिव फेडरेशन (एलपीएफ) और युनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (यूटीयूसी) शामिल हैं। बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की 'जन-विरोधी, श्रमिक-विरोधी, राष्ट्र-विरोधी और घातक नीतियों' के खिलाफ यह आम हड़ताल बुलायी गयी है। इसके अलावा केंद्रीय श्रम संगठनों ने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) के विरोध प्रदर्शन को भी अपना समर्थन दिया है। किसान हाल में संसद से पारित तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। वहीं बिजली (संशोधन) विधेयक 2020 रद्द करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्युत इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) ने भी 26 नवंबर को बिजली इंजीनियरों की हड़ताल की घोषणा की है।

कोरोना का असर

कुछ मंत्रालयों और विभागों का बजट अलोकेशन 30 फीसदी तक घटा

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना वायरस का असर इस बार देश के बजट पर भी साफ देखा जा रहा है। इस बार कुछ मंत्रालयों और विभागों के बजट मं 25-30 फीसदी तक की कटौती की गई है। सिर्फ जरूरी गतिविधियों वाले मंत्रालयों और विभागों को ही पूरा बजट दिया जा रहा है, जैसे हेल्थकेयर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत। इसकी वजह से मंत्रालयों और विभागों की दिए जाने कई भुगतान भी रोके जा रहे हैं।

करीब आधा बजट हो चुका है खर्च

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंत्रियों को कहा है कि वह सभी रिवाइज्ड एलोकेशन के हिसाब से खर्चे करें। वित्त वर्ष 2021 के लिए बजट में कुल 30,42,230 करोड़ रुपये खर्चे के लिए आवंटित किए गए थे और अप्रैल से सितंबर तक के बीच में इसमें से 48.6 फीसदी यानी 14,79,410 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि कोरोना का असर अगले साल के बजट पर भी पड़ सकता है, जिसे बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

राहत पैकेज में खर्च हो गया काफी पैसा

टैक्स कलेक्शन बढ़ने से कैश बढ़ा है, इसलिए मंत्रालयों और विभागों को खर्चे करने के लिए थोड़ी राहत दी गई है, लेकिन ओवरऑल खर्च को रिवाइज्ड बजट के हिसाब से ही देखना होगा। इस बार सरकार का बजट कम पड़ने की एक बड़ी वजह कोरोना की वजह से कम आमदनी तो है कि साथ ही चार पैकेज के जरिए लोगों को राहत मुहैया करना में भी सरकार का काफी पैसा खर्च हुआ है।

हेल्थ और डिफेंस को दी गई प्राथमिकता

अभी रिवाइज्ड बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए होने वाले खर्चों और कुछ डिफेंस की खरीद को सबसे ऊपर रखा गया है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि बजट में की गई कटौती इस बात पर भी निर्भर कर रही है कि किसी मंत्रालय ने कितना पैसे खर्च किया है। नए-नए बने मंत्रालय जल शक्ति ने सिर्फ 33 फीसदी बजट ही खर्च किया है, जिसे 30 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। वहीं पावर मिनिस्ट्री ने सिर्फ 28 फीसदी बजट खर्च किया है।

उद्योग जगत ने ब्रॉडबैंड की परिभाषा बदलने, सीमा दो एमबीपीएस तक बढ़ाने की मांग की

नयी दिल्ली। उद्योग संगठन बीआईएफ ने देश में ब्रॉडबैंड की परिभाषा बदलने की मांग की है। संगठन का कहना है कि यह बदलाव लंबे समय से लंबित है। अब समय आ गया है कि इसकी परिभाषा बदले और स्पीड की सीमा को मौजूदा 512 केबीपीएस से अढ़ाकर दो एमबीपीएस किया जाये। ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम (बीआईएफ) ने कहा कि पिछले कुछ सालों में संचार की प्रौद्योगिकी तेजी से बदली है। देश में डेटा सेवाओं का पूरी तरह से नया बाजार सामने आया है। अभी कई सारे ऐसे आधुनिक इंटरनेट उपकरण हैं और ऐसी जरूरतें हैं, जिनके लिये मौजूदा सीमा से अधिक स्पीड की जरूरत होती है। बीआईएफ ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से कहा, "हमारा यह मानना है कि ब्रॉडबैंड की मौजूदा परिभाषा न तो प्रौद्योगिकी के विकास के और न ही अधिक स्पीड वाली ब्रॉडबैंड सेवाओं की भारतीय उपभोक्ताओं की चाह के अनुकूल है। अतः ऐसे में निश्चित ही इसकी समीक्षा की जानी चाहिये और इसे बदला जाना चाहिये।" बीआईएफ ने नियामक के परामर्श पत्र 'ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और विस्तृत ब्रॉडबैंड स्पीड की रूपरेखा' को लेकर यह सुझाव दिया है। ट्राई ने 'क्या ब्रॉडबैंड की मौजूदा परिभाषा की समीक्षा किये जाने की जरूरत है' और 'क्या डाउनलोड व अपलोड स्पीड की सीमा को बदला जाना चाहिये' समेत विभिन्न मुद्दों पर संबंधित पक्षों की राय जानने के लिये यह परामर्श पत्र जारी किया था। बीआईएफ के अध्यक्ष टीवी रामाचंद्रन ने इस बारे में संपर्क किये जाने पर कहा कि 512 केबीपीएस स्पीड की मौजूदा परिभाषा काफी कम है। इसे बढ़ाकर दो एमबीपीएस किया जाना चाहिये। यह लंबे समय से लंबित है। बीआईएफ का कहना है कि 4जी आ जाने के बाद भी भारत में ब्रॉडबैंड स्पीड वैश्विक मानकों की तुलना में आधी है। संगठन ने कहा कि कम से कम दो एमबीपीएस की डाउनलोड व अपलोड स्पीड वाली इंटरनेट सेवाओं को ही ब्रॉडबैंड कहा जाना चाहिये।

हर्ष और उल्लास का महापर्व छठ

भारतवर्ष में पर्वों की एक गौरवशाली परंपरा रही है। युगों से भारतीय जनता विभिन्न प्रकार के पर्व-त्यौहार मना रही है। हर धर्म को मानने वालों के अपने-अपने पर्व और त्यौहार हैं। ऐसे सभी त्यौहारों का इतिहास हमारी धार्मिक अथवा सांस्कृतिक भावनाओं से संबंधित है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह सामाजिक वातावरण में सुख-दुःख का अनुभव करता है। खुशी का अनुभव करने के लिए विशेष अवसरों की खोज करता है और त्यौहार उन्हीं में से एक हैं। दीपावली, दशहरा, होली और रक्षाबंधन हमारे प्रमुख त्यौहार हैं, इन्हीं त्यौहारों में से एक प्रमुख त्यौहार है छठ। महाराष्ट्र का गणपति पूजा, गुजरात का गरबा, पंजाब का वैशाखी, असम का बिहू, केरल का ओणम, बंगाल का दुर्गा पूजा, इन त्यौहारों की तरह बिहार का छठ पूजा काफी लोकप्रिय है। छठ पर्व में डूबते व उगते हुए सूर्य की पूजा व आराधना की जाती है। धरती पर जीवन का आधार सूर्य है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार सूर्य आत्मा है तो चंद्रमा बल है। सूर्य पृथ्वी के उत्तरी भूभाग पर करीब नब्बे प्रतिशत रहता है। शेष दक्षिण भाग में समुद्र है इसमें सूर्य उत्तर भाग से दूर होता है, ऐसे में उत्तर भाग के रहने वाले सूर्य को नमन व प्रणाम करते हैं कि वह अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। छठ व्रत पौराणिक काल से ही चला आ रहा है। एक मान्यता के अनुसार महर्षि च्यवन की अस्वस्थता को देखकर उनकी युवा पत्नी सुकन्या ने सर्वप्रथम इस व्रत का शुभारंभ किया था। इस व्रत के प्रभाव से वृद्ध महर्षि पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए थे। तब से आज तक यह व्रत परंपरा में प्रचलित है। विद्वानों का कहना है कि जो व्यक्ति लगातार बारह वर्षों तक सूर्य (छठ) व्रत करता है उसका असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। छठ पर्व को महिलाएं तथा पुरुष दोनों करते हैं।

इस पर्व के प्रारंभ होने के बहत्तर घंटे पूर्व नहा-खाकर एक रस्म के साथ व नियम से छठ व्रत की शुरूआत होती है। पहले ही दिन से महिलाएं शुद्ध जल से स्नान करने के बाद (नहाय-खाय) एक रस्म के साथ छठ पूजा नियम करने लगती हैं। इस दिन से घर के लोग व व्रतधारी महिलाएं छठ के नियम का विधिवत पालन करने लगते हैं। व्रत होने वाले घरों में सफाई-पुताई की जाती है। पूजा का प्रसाद बनाने के लिए घर का एक कमरा सुरक्षित किया जाता है। उसमें केवल व्रत रखने वाले परिजन व महिलाएं ही प्रसाद सामग्री रखने या निकालने के लिए जाती हैं। उसके बाद महिलाएं सादगी, सफाई व पवित्रता का पूरा-पूरा ख्याल रखती हैं। उनका सब कार्य परिवार के सदस्यों से अलग हो जाता है। वे अपना भोजन अलग पकाती हैं। बर्तन, चूल्हा अलग रखती हैं। व्रती जमीन पर ही सोती हैं तथा कंबल या कुश की चटाई जमीन पर बिछाकर ही सोती हैं। पहले दिन सेंधा नमक, घी से बना अखा चावल और कद्दू की सब्जी को प्रसाद के रूप में वे ग्रहण करती हैं। घर के सभी व्यक्ति व्रती के भोजन करने के उपरांत ही भोजन करते हैं। व्रत में स्वच्छता का बहुत महत्व होता है, जिसके चलते साफ-सफाई का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है। पूजा में प्रयोग होने वाला खाद्य पदार्थ शुद्धता के मद्देनजर पकवान बनाने के लिए गेहूं को शुद्ध जल से धोकर छत पर या सुरक्षित स्थान पर सुखाया जाता है। सुखाते समय पूरा ध्यान रखा जाता है कि इसे कोई भी पशु-पक्षी या बच्चे जूठा न करें। उसके उपरांत साफ चक्की में गेहूं को पीसा जाता है। पिसे गेहूं के आटे से व्रती महिलाओं के पकवान जैसे पूड़ी, ठेकुआ तथा अन्य खाद्य सामग्री बनाई जाती है। इस पर्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उपासक महिलाएं निराजल व्रत यानि वह छत्तीस घंटा कुछ भी नहीं खा-पी सकती हैं।

पर्व के शुरू होने के दो दिन बाद व्रती महिलाएं शाम को घाट या पूजा स्थान पर डूबते हुए सूर्य को अर्ध्य चढ़ाती हैं। व्रती महिलाएं किसी नदी या तालाब में बने घाट पर पानी में खड़े होकर पूजा विधि पूरा करती हैं तथा सूर्य की उपासना करती हैं। घाट पर छठी मैया की पूजा-अर्चना करती हैं और वेदी पर धूप-दीप व अन्य पूजा सामग्री अर्पण करती हैं।

दूसरे दिन सुबह घाट पर पूजा स्थान पर बहुत जल्दी पहुंचना अनिवार्य होता है। उगते हुए सूर्य को अर्ध्य देने के लिए तड़के व्रतधारियों की भीड़ घाटों व पूजा स्थानों पर जुटनी शुरू हो जाती है। इस समय इन स्थानों पर अपना एक अलग ही दृश्य होता है। भक्तगण एक लाईन में खड़े होकर सूर्य के उगने का इंतजार करते हैं और जैसे ही सूर्य दिखाई पड़ता है सूर्य को अर्ध्य देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके बाद व्रतधारी महिलाएं अन्न व जल को ग्रहण करती हैं। एक-दूसरे को प्रसाद बांटती हैं। इस प्रकार चार दिन तक चलने वाले छठ महापर्व का समापन होता है।

छठ पूजा 2020

षष्ठी देवी देती हैं 6 बड़े शुभ आशीर्वाद

ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में बताया गया है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक प्रमुख अंश को 'देवसेना' कहा गया है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इस देवी का एक प्रचलित नाम षष्ठी है। पुराण के अनुसार, ये देवी सभी 'बालकों की रक्षा' करती हैं और उन्हें लंबी आयु प्रदान करती हैं। आज भी ग्रामीण समाज में बच्चों के जन्म के छठे दिन षष्ठी पूजा या छठी पूजा का प्रचलन है।

"षष्ठांशा प्रकृतेर्या च सा च षष्ठी प्रकीर्तिता।
बालकाधिष्ठातृदेवी विष्णुमाया च बालदा।।
आयुःप्रदा च बालानां धात्री रक्षणकारिणी।
सततं शिशुपार्श्वस्था योगेन सिद्धियोगिनी।।"
-(ब्रह्मवैवर्तपुराण,प्रकृतिखंड ४३/४/६)

षष्ठी देवी को ही स्थानीय भाषा में छठी मैया कहा गया है। षष्ठी देवी को 'ब्रह्मा की मानसपुत्री' भी कहा जाता है।

मां कात्यायनी ही हैं छठी मैया

पुराणों में छठी मैया का एक नाम कात्यायनी भी है। इनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि को होती है। शेर पर सवार मां कात्यायनी की चार भुजाएं हैं। वह बाएं हाथों में कमल का फूल और तलवार धारण करती हैं। वहीं, दाएं हाथ अभय और वरद मुद्रा में रहते हैं। मां कात्यायनी योद्धाओं की देवी हैं। राक्षसों के अंत के लिए माता पार्वती ने कात्यायन ऋषि के आश्रम में ज्वलंत स्वरूप में प्रकट हुई थीं, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। छठी मैया भगवान सूर्य की बहन हैं। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है।

छठी मैया से मिलते हैं ये 6 बड़े आशीर्वाद

1. छठी मैया का पूजा करने से निःसंतान दंपत्तियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है।
2. छठी मैया संतान की रक्षा करती हैं और उनके जीवन को खुशहाल रखती हैं।
3. छठी मैया की पूजा से कई पवित्र यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है।
4. परिवार में सुख, समृद्धि, धन संपदा और परस्पर प्रेम के लिए भी छठी मैया का व्रत किया जाता है।
5. छठी मैया की पूजा से विवाह और करियर संबंधी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
6. छठी मैया के स्मरण से घर से निर्धनता दूर होती है। धन संपदा का मिलता है आशीष।

छठी मैया का नियम पूर्वक व्रत करने से व्रत सम्पूर्ण फल प्राप्त होता है। नियम को उल्लंघन करने से उसका कुफल भी मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि राजा सगर ने सूर्य षष्ठी व्रत सही तरह से नहीं किया था इसलिए उनके 60 हजार पुत्र मारे गए थे।

इन चीजों के बिना अधूरी मानी जाती है छठ पूजा, जानें पूजन सामग्री की संपूर्ण सूची

छठ पर्व की शुरुआत इस वर्ष 18 नवंबर, 2020 से हो रही है। छठ पूजा में सामग्री का संपूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है तब ही छठ व्रत पूर्ण होता है। छठ व्रत विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं/ पुरुष निर्जल व्रत करते हैं। छठ व्रत सामग्री का बहुत महत्व होता है। छठी मैया को कई प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। इसमें फल-सब्जियां सहित बहुत सी सामग्री जरूरी होती है। आइए जानते हैं छठ पूजा सामग्री....

छठ पूजा सामग्री

■प्रसाद के लिए बांस की तीन टोकरी ■बांस या पीतल के तीन सूप ■लोटा, थाली ■गिलास ■नारियल ■साड़ी-कुर्ता पजामा ■गन्ना पत्तों के साथ ■हल्दी अदरक हरा पौधा ■सुथनी ■शकरकंदी ■डगरा ■हल्दी और अदरक का पौधा ■नाशपाती ■नींबू बड़ा ■शहद की डिब्बी ■पान सुपारी ■कैराव ■सिंदूर ■कपूर ■कुमकुम ■अक्षत के लिए चावल ■चन्दन ■ठेकुआ, मालपुआ ■खीर-पूड़ी ■खजूर ■सूजी का हलवा ■चावल का बना लड्डू/लड्डुआ ■सेब ■सिंघाड़ा ■मूली।

छठ पर्व की पूजा के 4 दिन के 4 कार्य

इस बार छठ पर्व 18 नवंबर से 20 नवंबर 2020 के मध्य मनाया जाएगा। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का प्रचलन और उन्हें अर्ध्य देने का विधान है। यह पर्व दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। छठ पूजा का व्रत महिलाएं अपनी संतान की रक्षा और पूरे परिवार की सुख शांति का वर मांगाने के लिए करती हैं। मान्यता अनुसार इस दिन निःसंतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हैं छठ मैया।

छठ पूजा व व्रत का प्रारंभ हिन्दू माह कार्तिक माह के शुक्ल की चतुर्थी तिथि से होता है और षष्ठी तिथि को कठिन व्रत रखा जाता है तथा दूसरे दिन सप्तमी को इसका पारण होता है। दरअसल, छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला पर्व है जिसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है और कार्तिक शुक्ल सप्तमी को इस पर्व का समापन होता है। आओ इन चार दिनों में क्या खास करते हैं।

1. **नहाय खाये :** पहले दिन नहाय खाये अर्थात साफ-सफाई और शुद्ध शाकाहारी भोजन सेवन का पालन किया जाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी अर्थात इसी दिन से छठ पर्व प्रारंभ हो जाता है। इस दिन से घर और शरीर को भीतर और बाहर से शुद्ध किया जाता है। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं किया जाता है।
2. **खरना :** दूसरे दिन खरना अर्थात पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर, घी लगी हुई रोटी और फलों का सेवन करते हैं। इस पूरे दिन जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। संध्या को खाया जाता है उसे घर के अन्य सदस्यों को प्रसाद रूप में दिया जाता है।
3. **संध्या अर्घ्य :** छठ का यह तीसरा दिन महत्वपूर्ण होता है। इस दिन कार्तिक शुक्ल की षष्ठी होती है। संध्या षष्ठी को अर्घ्य अर्थात संध्या के समय सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और विधिवत पूजन किया जाता है। शाम को बांस की टोकरी में ठेकुआ, चावल के लड्डू और कुछ फल रखें जाते हैं और पूजा का सूप सजाया जाता है और तब सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इसी दौरान सूर्य को जल एवं दूध चढ़ाकर प्रसाद भरे सूप से छठी मैया की पूजा भी की जाती है। बाद में रात्रि को छठी माता के गीत गाए जाते हैं और व्रत कथा सुनी जाती है।
4. **उषा अर्घ्य :** उषा अर्घ्य अर्थात इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। पूजा के बाद व्रति कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत को पूरा करती हैं, जिसे पारण या परना कहा जाता है। यह छठ पर्व का समापन दिन होता है।

यह मुख्य रूप से यह लोकपर्व है जो उत्तर भारत के राज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लोग ही मनाते हैं। यहां के लोग देश में कहीं भी हो वे छठ पर्व की पूजा करते हैं।

किसानों के लिए होने वाले रिसर्च में ड्रोन का होगा उपयोग, सरकार से मिली हरी झंडी

नई दिल्ली। एजेंसी

*खेती-बाड़ी के क्षेत्र में अनुसंधान **(Agri Research)** के लिए अब ड्रोन **(Drone)** की मदद भी ली जा सकेगी। इसके लिए यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री **(Civil Aviation Ministry)** की अनुमति मिल गई है। यह अनुमति तेलंगाना के हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीच्यूट **(ICRISAT)** को मिली है। वह अब सशर्त ड्रोन की तैनाती कर सकेंगे। इसका उपयोग कृषि कार्य के लिए ही होगा।*

खेती-बाड़ी में भी ड्रोन की होगी बड़ी भूमिका

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के संयुक्त सचिव अंबर दुबे का कहना है कि ड्रोन भारत के कृषि क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यह विशेष रूप से उचित कृषि (precision agriculture), टिड्डी नियंत्रण (locust control) और फसल उपज में सुधार लाने (improvement in crop yield) जैसे क्षेत्रों में विशेष काम देगा। इस समय सरकार युवा उद्यमियों और शोधकर्ताओं को देश के 6.6 लाख से भी अधिक गांवों में कम कीमत के ड्रोन सोल्यूशन प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

कब तक के लिए मिली है छूट

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के मुताबिक यह सशर्त छूट इस आशय का पत्र जारी होने की तिथि से छह माह की अवधि के लिए या डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म (चरण-1) के पूर्ण परिचालन तक, जो भी पहले हो, मान्य होगी। यह छूट तभी मान्य होगी, जब सरकार द्वारा तय की गई सभी शर्तों और सीमाओं का सख्ती से अनुपालन किया जाए। किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह छूट समाप्त हो जाएगी।

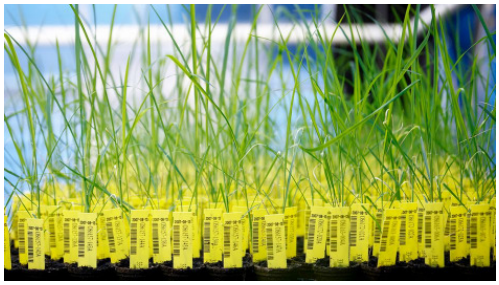

जीएम फसल से तैयार प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के आयात पर रोक लगाने की जरूरत : एसजेएम

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से जीएम फसल से निर्मित प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। एफएसएसएआई अध्यक्ष को एक पत्र में एसजेएम के सह संयोजक अश्विनी महाजन ने कहा कि गोपनीय तरीके से देश में जीएम खाद्य उत्पादों को लाना गैर कानूनी है और यह राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है । महाजन ने कहा कि चूंकि देश में जीएम आधारित खाद्य फसलों को उगाने की अनुमति नहीं है इसलिए इन फैसलों से तैयार खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के खाद्य पदार्थ का आयात किया जाता है तो सुरक्षा को लेकर विभिन्न एजेंसियों द्वारा व्यापक आकलन के बाद इसकी अनुमति होनी चाहिए। महाजन ने कहा कि पर्यावरण और वन मंत्रालय की आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति (जीईएसी) के साथ ही इसमें एफएसएसएआई को भी शामिल करना चाहिए । उन्होंने कहा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे कई निर्यातक देश भी दलील दे रहे हैं कि वैश्विक बाजार में बेचे जा रहे जीएम खाद्य उत्पाद पारंपरिक उत्पादों की तरह ही सुरक्षित हैं लेकिन एफएसएसएआई को ऐसे उत्पादों को अनुमति नहीं देनी चाहिए । उन्होंने कहा कि एसजेएम का मानना है कि जीएम सोयाबीन तेल और जीएम कनोला तेल के लिए पूर्व में जीईएसी द्वारा दी गयी अनुमति को भी नियामकीय संस्था को वापस लेना चाहिए ।

डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स को सरकार का फरमान

एक महीने में करना होगा यह काम

नई दिल्ली। एजेंसी

डिजिटल माध्यमों से खबर या समसामयिक विषयों का प्रकाशन/प्रसारण करने वाली इकाइयों के लिए सरकार ने सोमवार को नए दिशानिर्देश जारी किए। इसके तहत उन्हें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों का अनुपालन करने के लिए एक माह का समय दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को सोमवार को ये निर्देश जारी किए। ऐसी कंपनियों में 26 प्रतिशत तक विदेशी हिस्सेदारी की छूट दी गई है।

मंत्रालय ने न्यूज पोर्टलों, वेबसाइटों और न्यूज एजेंसियों को जारी किए गए नोटिस में कहा है कि प्रासंगिक निकायों को एक महीने के भीतर दिशानिर्देशों पर अमल करना होगा। मंत्रालय ने नोटिस में दिशानिर्देशों का ब्योरा दिया है जिसका अनुपालन किया जाना है। गौरतलब है कि सरकार ने डिजिटल माध्यमों में एफडीआई संबंधी निर्देश 18 सितंबर 2019 को जारी किए थे। नोटिस में कहा गया, 'जिन निकायों में एफडीआई 26 प्रतिशत से कम है, उन्हें एक महीने के भीतर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सूचना देनी होगी। सूचना में निदेशकों व शेयरधारकों का नाम तथा पता के साथ कंपनी और उसकी शेयरधारिता की जानकारी देनी होगी।'

प्रावधानों का पालन

मंत्रालय ने ऐसे निकायों को अपने प्रवर्तकों तथा महत्वपूर्ण लाभार्थी स्वामियों के नाम एवं पते देने के लिए भी कहा गया है। इन निकायों को एफडीआई नीति, विदेशी विनिमय प्रबंधन (गैर-ऋण प्रतिभूतियां) नियम 2019 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण प्रतिभूतियों के भुगतान एवं विवरण प्रस्तुत करने का ढंग) विनियम 2019 के तहत मूल्य निर्धारण, दस्तावेजीकरण और सूचना देने के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। नोटिस में कहा गया, 'जिन निकायों में अभी 26 प्रतिशत की सीमा से अधिक एफडीआई है, उन्हें भी आज से एक महीने के भीतर मंत्रालय को ये तमाम सूचनाएं देनी पड़ेंगी। इन निकायों को 15 अक्टूबर 2021 तक एफडीआई को 26 प्रतिशत से नीचे लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे और मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त करनी होगी।' सरकार ने यह नोटिस ऐसे समय जारी किया है, जब उच्चतम न्यायालय ने नेटफ्लिक्स और ऐमजॉन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के नियमन के लिए दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र सरकार को एक महीने पहले नोटिस दिया था।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को अधिकार

सरकार हाल ही में नेटफ्लिक्स, ऐमजॉन प्राइम वीडियो और डिजनीह्ट हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म तथा ऑनलाइन खबर व करंट अफेयर्स देने वाले पोर्टलों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाई है। मंत्रालय को अब डिजिटल क्षेत्र के लिए नियम व नीतियां बनाने की शक्ति दी गई है। मंत्रालय ने सोमवार को जारी नोटिस में यह भी कहा कि यदि कोई निकाय देश में नया एफडीआई लाना चाहता है, तो उसे डीपीआईआईटी के विदेशी निवेश क्रियान्वयन पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

चीनी उत्पादन 15 नवंबर तक करीब तीन गुना बढ़कर 14.10 लाख टन : इस्मा

नई दिल्ली। दुनिया में चीनी के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश, भारत में चीनी का उत्पादन चीनी सत्र 2020-21 पेराई मौसम में 14 लाख लाख टन तक पहुंच गया है जो पिछली साल इसी समय से तीन गुना है। चीनी उद्योग के प्रमुख संगठन, भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) ने मंगलवार को बताया कि बेहतर फसल उत्पादन और पेराई अभियान के समय पर शुरू होने की वजह से उत्पादन में वृद्धि हुई है। इस्मा ने कहा कि चीनी सत्र 2019-20 (अक्टूबर-सितंबर) की समान अवधि में चीनी का उत्पादन 4.84 लाख टन रहा था। चूंकि भारत में एक बार और अधिशेष चीनी उत्पादन होने जा रहा है, इसलिए उद्योग निकाय इस्मा ने कहा कि वह चीनी निर्यात के बारे में सरकार के नीतिगत फैसले का इंतजार कर रहा है और सब्सिडी समर्थन के साथ बफर स्टॉक निर्माण के बारे में भी फैसले के इंतजार में है।

इस्मा के अनुसार, पिछले साल की तुलना में, महाराष्ट्र और कर्नाटक में अच्छी बारिश और जलाशयों में पर्याप्त पानी की उपलब्धता, गन्ने की अधिक पैदावार और बेहतर उपज की वजह से गन्ने की बेहतर उपलब्धता के कारण, अक्टूबर 2020 के अंतिम सप्ताह के दौरान पेराई सत्र की अच्छी शुरुआत हो सकी है। चालू सत्र में 15 नवंबर तक 271 चीनी मिलें परिचालन में थीं, जबकि एक साल पहले इसी दौरान 127 चीनी मिलें परिचालन कर रही थीं। कुल चीनी उत्पादन में, देश के अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य - उत्तर प्रदेश में मिलों ने 15 नवंबर तक 3.85 लाख टन चीनी का उत्पादन किया,

जो कि एक साल पहले की अवधि में 2.93 लाख टन चीनी उत्पादन से अधिक है। देश के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में मिलों ने चालू सत्र में अब तक 5.65 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है। पिछले सत्र की समान अवधि में, सूखा होने और कम गन्ने के कारण पेराई का काम काफी देर से नवंबर के चौथे सप्ताह में शुरू हुआ था। इसी प्रकार कर्नाटक में चीनी का उत्पादन पिछले वर्ष की अवधि में 1.43 लाख टन से बढ़कर 3.40 लाख टन हो गया। अन्य राज्यों में, गुजरात में चीनी उत्पादन चालू सत्र में 15 नवंबर तक 80,000 टन तक जा पहुंचा, जबकि पिछले साल यह उत्पदन 2,000 टन था। उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगभग 18 कारखानों ने पेराई कार्य शुरू किया है और चालू मौसम में 15 नवंबर तक 40,000 टन चीनी का उत्पादन किया है। भारत में एक और अधिशेष चीनी वर्ष होने की बात कहते हुए इस्मा ने कहा कि अधिशेष चीनी के लगभग 60-70 लाख टन हिस्से का निर्यात जारी रखने की आवश्यकता है। इसने कहा है कि चीनी सत्र 2020-21 में 106.4 लाख टन के पिछले साल के बचे स्टॉक तथा चालू सत्र में 310 लाख टन के उत्पादन अनुमान को देखते हुए, आपूर्ति के लिए अधिक चीनी होगी। इथेनॉल पर, इस्मा ने कहा कि चीनी मिलों ने वर्ष 2019-20 के चीनी सत्र (दिसंबर-नवंबर) के नौ नवंबर तक 160.23 करोड़ लीटर इथेनॉल की आपूर्ति की है। चीनी सत्र 2020-21 में, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने चीनी मिलों से लगभग 322.57 करोड़ लीटर इथेनॉल के लिए प्राप्त प्रस्तावों के मुकाबले लगभग 262.27 करोड़ लीटर का आवंटन किया है।

इन्टास फार्मास्यूटिकल्स ने रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाली पैटन्टड 'थाइमोटास' दवाई लॉन्च की

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

इन्टास ने रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाली और संक्रमण के उपचार में सफलता सुनिश्चित करने वाली थाइमोक्विनोन की एक नवीनतम और सायन्टिफिक फॉर्म्यूलेशन संशोधात्मक रचना 'थाइमोटास'लॉन्च की है। थाइमोटास कोविड-19 के मानक उपचार में असरकारक सहायक के तौर पर नैदानिक रुप से परीक्षण किया गया है। थाइमोक्विनोन (थाइमोटास) नाइजेला सटिवा (जिसको कलौंजी एवं काली जीरी के नाम से भी जाना जाता हैं) के एक्टिव बायोलॉजिकल कोम्पोनन्ट है। थाइमोक्विनोन के लाभकारी औषधीय गुणों साबित करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक प्रकाशन उपलब्ध है। इन्टास द्वारा विश्व में पहलीबार थाइमोक्विनोन को स्थिर,मानकीकृत और रेडी-टु-युज टैब्लट के रुप में विकसित किया गया है।

थाइमोटास एंटी-वायरल, एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी और एंटीऑक्सिडेंट के तौर पर रोग प्रतिरोधक शक्ति को मज़बूत करता है और संक्रमण से लड़ता है। SARS-CoV2 के सामने इन-विट्रो एंटीवायरल परिक्षण के माध्यम से थाइमोटास के एंटी वायरल प्रभाव की जांच कि गई है, जिसमें कोविड-19 के मानक उपचार में सहायक दवाई के तौर पर प्रयोग की ज़बर्दस्त संभावना हैं। सिनियर वाइस प्रेसिडन्ट और मेडिकल अफेर्स के हेड डॉ. आलोक चतुर्वेदी ने कहा कि, 'वर्तमान महामारी के समय में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने और संक्रमण के सामने लड़ने के लिए थाइमोटास 12.5 मिलिग्राम प्रभावी रुप से बहुत उपयोगी है' डबल्यू.एच.ओ.-जी.एम.पी. सर्टिफाइड प्लान्ट में निर्मित थाइमोटास रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने एवं संक्रमण रोकने में उपचारक के तौर पर हर रोज़ भोजन के बाद 12.5 मिलिग्राम की एक टैब्लट या डॉक्टर से परामर्श अनुसार प्रयोग करने की सिफारिश की जाती है। डॉक्टर के परामर्श अनुसार या संक्रमण की तीव्रता के अनुसार मानक सहायक दवाई के तौर पर थाइमोटास टैब्लट की भोजन के बाद हर रोज़ 50 मिलिग्राम तक प्रयोग करने की सिफारिश की जाती है। थाइमोटास दवाई को पुरा ही निगलें, तोड़े या चबाएं नहीं।

सिप्ला ने कोविड-19 एंटीबॉडी परीक्षण किट के लिए बेल्जियम की मल्टीजी के साथ समझौता किया

नयी दिल्ली। एजेंसी

दवा कंपनी सिप्ला ने बुधवार को कहा कि उसने कोविड-19 एंटीबॉडी परीक्षण किट के वितरण के लिए बेल्जियम की कंपनी मल्टीजी के साथ लाइसेंस समझौता किया है। यह समझौता ज्यादातर उभरते बाजारों और यूरोप के लिए है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि यह लाइसेंस समझौता जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवन रक्षक उपचार और नैदानिक बुनियादी ढांचा बढ़ाने के उसके प्रयासों का हिस्सा है। कंपनी ने बताया, "इस समझौते के तहत सिप्ला कोविड-19 रैपिड एंटीबॉडी किट का वितरण करेगी, जिसका विनिर्माण मल्टीजी करेगी।" सिप्ला ने बताया कि मल्टीजी के रैपिड एंटीबॉडी किट को 'कोवी-जी' ब्रांड नाम से बेचा जाएगा।

अब डेंगू और मलेरिया के लिए भी मिलेगी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी

नई दिल्ली। एजेंसी

स्वास्थ्य और साधारण बीमा कंपनियों को जल्दी ही मच्छर और कीटाणुओं से होने वाली डेंगू, मलेरिया और चिकुनगुनिया जैसी बीमारियों (वेक्टर जनित बीमारी) के इलाज के लिये बीमा कवर उपलब्ध कराने की अनुमति मिलेगी। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) वेक्टर जनित बीमारी के मानकों को लेकर मसौदा जारी किया है। इसमें डेंगू और मलेरिया समेत कई बीमारियों का कवर शामिल होगा।

मानक स्वास्थ्य बीमा का लक्ष्य

इरडा ने कहा कि इसका मकसद एक मानक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद लाना है जो लोगों की वेक्टर जनित बीमारियों के इलाज को शामिल करे। प्रस्ताव के तहत बीमा पॉलिसी की अवधि एक साल होगी और इसमें प्रतीक्षा अवधि 15 दिन की होगी। नियामक ने संबंधित पक्षों से मसौदे पर 27 नवंबर तक अपनी राय देने को कहा है।

इन बीमारियों का होगा कवर

बीमा पॉलिसी में डेंगू बुखार, मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजर, चिकुनगुनिया, जापानी बुखार और जाइका विषाणु के इलाज को शामिल किया जाएगा। मौजूदा समय में अलग से इन बीमारियों का कोई बीमा कवर नहीं है। साथ ही मौजूदा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में भी कंपनियां अपनी सुविधा के तहत कवर देने या नहीं देने का फैसला करती हैं। साथ ही उनमें कई तरह की शर्तें भी होती हैं।

कंपनियां भी होगीं प्रोत्साहित

बीमा नियामक का कहना है कि प्रस्तावित मसौदे के तहत आने वाली बीमा पॉलिसी से साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियां एक साल के लिए इस प्रकार की पॉलिसी की पेशकश के लिए प्रोत्साहित होंगी। बीमा बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि इरडा के इस फैसले उपभोक्ताओं के लिए इन बीमारियों के लिए पॉलिसी का चुनाव करना आसान हो सकता है। साथ ही एक मानक होने से क्लेम को लेकर कंपनियां भी मनमानी नहीं कर पाएंगी।

कोरोना ने दिखाई राह

कोरोना के लिए अलग से बीमा पॉलिसी नहीं थी। ऐसे में शुरुआत में क्लेम को लेकर आ रही परेशानियों को देखते हुए बीमा नियामक इरडा ने कंपनियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि मौजूदा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत इसे कवर दें। इसके बाद इरडा ने कोरोना के लिए विशेष रूप से कोरोना कवच और कोरोना सुरक्षा नाम से मानक पॉलिसी देने की मंजूरी दी। इसमें 50 हजार रुपये से पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। इसकी अवधि साढ़े तीन माह से साढे नौ माह तक है।

ग्रीन प्लान के तहत वर्ष 2030 से पेट्रोल-डीजल कारों की ब्रिकी बैन करेगा ब्रिटेन

लंदन। एजेंसी

ग्रीन इंडिस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंतर्गत ब्रिटेन वर्ष 2030 से डीजल और पेट्रोल की कारों की बिक्री (Petrol and Diesel vehicle sales) पर प्रतिबंध लगाएगा। यह ब्रिटेन की 10 बिंदुओं के प्लान का हिस्सा है जिसका खुलासा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Prime Minister Boris Johnson) ने बुधवार को किया। ब्रिटिश पीएम ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 12 बिलियन पाउंड की राशि तय की है, उम्मीद है कि इससे दो लाख 50 हजार नए रोजगार पैदा होंगे और इस योजना के फलस्वरूप वर्ष 2050 तक ब्रिटेन को कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा।

प्रस्ताव में पवन ऊर्जा के उत्पादन को चार गुना तक बढ़ाने और उद्योग, परिवहन, ऊर्जा और घरों के लिए हाइड्रोजन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने का प्रावधान भी रखा गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 'शून्य कार्बन उत्सर्जन' के लिए भी निवेश का प्रावधान किया गया है। प्लेन्स और शिप्स के लिए भी ऐसी ही योजना है। इसके साथ ही साइकिलिंग और वॉकिंग को प्रोत्साहित करने के उपायों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

सरकार बड़े और छोटे स्तर के न्यूक्लियर प्लांट के विकास और नए एडवांस्ड मॉड्युलर रिएक्टर के लिए 525 मिलियन पाउंड की राशि खर्च करेगी। हालांकि उसका यह कदम पर्यावरणविदों को नाखुश कर सकता है। पीएम जॉनसन को उम्मीद है कि इस महत्वाकांक्षी प्रस्ताव से ब्रिटेन की क्षेत्रीय असमानता को कम करने और कोरोना महामारी के कारण हुए आर्थिक नुकसान को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।